Central Investment subsidy from 15 per cent to 20 per cent in respect of industrial units set up in notified districts in North Eastern Region including Assam.

Setting up of mini Cement plants in Maharashtra

380. SHRI UTTAM RATHOD: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether former Minister of Industries had declared on the Floor of the House that Maharashtra will have two mini cement plants;

(b) if so, which are the places selected for these plants; and

(c) what is the progress achieved after the pronouncement of this policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) to (c). The policy of the Government has been to encourage setting up of mini cement plants in the country. Letters of intent have been granted to the following three parties for setting up of mini cement plants in the State of Maharashtra:—

Name of the Scheme	Location	Capacity in lakh tonnes	Date of letter of intent
Hariganga Cement Ltd.	Rajura	0·66	16-4-1980
Shri Nem Kumar Kesharimal Porwal & Sushil Kumar, Nem Kumar Porwal, Post Kamtu	Rajura Distt. Chandrapur	0·60	28-8-1980
Agrima Engineering & Consultancy Services Ltd.	Rajura	0.66	28-7-1980

One more scheme for setting up of a mini cement plant for a capacity of 9,000 tonnes at Chandrapur has been registered with DGTD.

मैसर्स इंडिया पेपर कम्पनी लि० हाजीनगर पश्चिम बंगाल का बन्द किया जाना

381. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इंडिया पेपर पल्प कम्पनी लि०, हाजीनगर 24-परगना पश्चिम बंगाल के बन्द हो जाने के कारण इसके 1700 कर्मचारी भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ;

(ख) क्या इस कम्पनी का प्रबन्ध जून, 1976 की आपातकालीन अवधि के दौरान हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० को सौंप दिया गया था ताकि अन्ततः इसका प्रबंध सरकार अपने हाथ में ले ले ;

(ग) क्या इसे पुनः चाल करने के लिये जनता सरकार ने 6.64 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी और 29 जुलाई, 1979 की यह राशि बढ़ाकर 10.13 करोड़ रुपये कर दी गई थी ;

(घ) क्या उन्होंने उक्त कम्पनी को सरकार के प्रबंधाधिकार से लेने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की थी और उक्त समिति अपना प्रतिवेदन 1980 में दे चुकी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस कम्पनी को अपने अधिकार में लेने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) चूंकि इंडिया पेपर पल्प कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय